संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री का भाषण

25 अक्तूबर, 2009

मैंने सातवें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की वार्ताओं के दो अति महत्वपूर्ण दिन पूरे किये हैं।

मैं भारत-आसियान शिखर वार्ता के नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैंने आसियान देशों की भारत के साथ सभी क्षेत्रों में अपने संबंध मजबूत करने की प्रबल इच्छाशक्ति महसूस की। इसमें न केवल आर्थिक सहयोग और व्यापार शामिल हैं, बल्कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण सुरक्षा और अधिक गहन राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी शामिल हैं।

भारत-आसियान माल व्यापार समझौता होने से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ एवं एकीकृत करने की ओर भारत के कदम आगे बढ़े हैं। इस करार के अनुवर्तन के रूप में हम एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एण्ड इनवेस्टमेन्ट को अंतिम रूप देने के लिए राज़ी हुए हैं।

आसियान देशों ने भारत द्वारा घोषित की गई नयी पहलों, खासकर भारत-आसियान गोल मेज की स्थापना, वर्ष 2020 तक हमारे संबंधों के लिए विजन स्टेटमेन्ट को तैयार करना, वर्ष 2012 में यादगार घटनाओं को याद करना, और आसियान कार्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-2015 की समयावधि के लिए 5 करोड़ अमरीकी डालर की धनराशि की सहायता करने की हमारी पेशकश की काफी तारीफ की।

पूर्वी एशिया शिखर वार्ता के दौरान मैंने एक ऐसे एशियाई आर्थिक समुदाय की परिकल्पना के बारे में अपने विचार रखे जो एक खुले और सर्वनिहित क्षेत्रीय ढांचे पर आधारित हो। पूर्वी एशियाई देश वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में भारत में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों के असर और एशिया के अपने विकास में रफ्तार लाने के लिए भारत में छिपी संभावनाओं को मान्यता देते हैं। मैंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तत्काल सहयोग की आवश्यकता, एशिया को खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया क्योंकि सतत विकास की ओर का रास्ता ढूंढने में इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती

है। हमने इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बात पर भी सहमति हुई कि आतंकवाद के मुद्दे और सुरक्षा के प्रति गैर-पारंपरिक खतरों से दृढ़-निश्चय के साथ निपटना होगा।

पूर्वी एशिया शिखर वार्ता में शामिल नेताओं द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना, जो बिहार में स्थित होगा, को स्वीकार करना अत्यंत संतोष का विषय है। हम अगले कदम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के एक केन्द्र के रूप में करना चाहते हैं।

चीन, जापान, थाइलैंड, कम्बोडिया, सिंगापुर और वियतनाम के नेताओं के साथ मेरी बैठकें काफी महत्वपूर्ण रहीं, और मैं कुछ ही समय में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिलूंगा। ये बैठकें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सहयोगात्मक भागीदारियां स्थापित करने की हमारी इच्छा शक्ति और एशिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता स्थापित करने की ओर हमारी सही भूमिका प्रदर्शित करता है।

मैं इस बात से आश्वस्त होकर भारत लौट रहा हूं कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में भारत की काफी अच्छी साख है और इस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं।

***